on an year to year basis in tune with the allocations made under the Rural Landless Employment Guarantee Programme.

राज्यों में पंचायत चुनाव

234. **श्री अजीत जोगी** : क्या कृषि मंत्री 12 अगस्त, 1988 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2181 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य किन-किन राज्यों में अब तक पंचायत चुनावों की घोषणा की जा चुकी है ;

(ख) वे कौन-कौन से राज्य हैं जो इस संबंध में प्रधान मंत्री और केन्द्रीय सरकार द्वारा सुझाव दिए जाने के बाद भी पंचायत चुनाव नहीं करा रहे हैं ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार सभी राज्यों में यथासंभव शीघ्र पंचायत चुनाव कराना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार पंचायतीराज संस्थाओं के नियमित अंतरालों पर चुनाव कराने के लिए राज्यों से आग्रह कर रही है। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर पंजाब में ग्राम पंचायतों के चुनाव शीघ्र ही कराये जाने की संभावना है। अन्य राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार और जम्मू और कश्मीर जहां पंचायतों के चुनाव होते रहते हैं, ने अभी चुनावों की घोषणा नहीं की है।

"सेल" (स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड) द्वारा कमाया गया मुनाफा

235. **श्री अजीत जोगी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1987-88 के वर्ष के दौरान स्टील अथारिटी आफ इंडिया ने 63 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया जो इसके द्वारा पिछले वर्ष कमाये गये मुनाफे से अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सभी इस्पात संयंत्रों की कार्य प्रणाली से संतुष्ट है ; और

(ग) विकसित देशों की तुलना में भारत में इस्पात के उत्पादन में अधिक लागत के अन्तर्ग्रस्त होने की बात को ध्यान में रखते हुए इन इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) जी, हां। वर्ष 1987-88 के दौरान स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल) को 63.27 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था।

(ख) और (ग) यद्यपि यह संतोषजनक बात है कि "सेल" का कार्यनिष्पादन उत्कृष्ट है, तथापि और प्रगति की गुंजाइश को ध्यान में रखते हुए सरकार दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो इस्पात संयंत्रों तथा इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के बर्नपुर कारखाने को आधुनिक बनाने की योजना बना रही है। इसके परिणामस्वरूप प्रौद्योगिकियां उन्नत होंगी, वर्तमान सुविधाओं का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित होगा, ऊर्जा की खपत तथा निर्माण कार्य की लागतों में कमी आएगी तथा उत्पादकता में सुधार होगा।

Prime Minister's Visit to the Flood Affected States

236. SHRI YASHWANT SINHA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Prime Minister has visited the flood-affected States in the country during the past few months;

(b) if so, the names of the flood affected States visited by the Prime

Minister and also those not visited by the Prime Miniser;

(c) the States in which the Prime Minister found the relief work to be satisfactory and the States in which he found them to be unsatisfactory; and

(d) the financial assistance granted by the Centre to the various States to meet the situation arising out of the floods as grants and loans, separately, State-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHYAM LAL YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) During the South-west monsoon of 1988, 21 States, *Viz.*, Andhra Pradesh, Arunacha Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Orissa, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tripura, U.P., West Bengal, and Mizoram have reported damages due to floods and heavy rains, etc. Prime Minister visited the flood affected States of Assam, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Jammu & Kashmir.

(c) Substantial relief work is being done by the State Governments in accordance with the severity of the flood and local problems and within the financial and other constraints being faced by them. Wherever any lacunae were noticed in the relief works being organised by the State Governments; the same were pointed out to them for corrective action. It is not possible to compare the quality of relief works organised by different States as the circumstances, dimensions of the problem and constraints vary from State to State.

(d) 17 out of 21 States affected have submitted memoranda seeking Central assistance for flood relief. On the basis of the report of the Central Team and recommendations of the High Level Committee on Relief, a ceiling of expenditure of Rs.. 28.76 crores to Andhra Pradesh, Rs. 85.36 crores to Assam, Rs. 27.02 crores to Gujarat, Rs. 31.14 crores to Haryana, Rs. 14.46 crores to Jammu & Kashmir for first wave, Rs. 10.55 crores to Kerala, Rs. 8.49 crores to Sikkim (including earthquake) and Rs. 23.55 crores to West Bengal have been approved so far. The ceiling of expenditure to the remaining States will be approved as per laid down procedure. A non-Plan grant to the extent of Rs. 75 per cent of the total ceiling of expenditure approved in excess of Margin money, is provided for flood relief in the affected States.

Pending Case in Delhi Industrial Tribunals

237. SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Industrial disputes covering from six years to ten years are pending for disposal in Delhi Industrial Tribunals;

(b) if so, the number of the disputes pending in each Tribunal covering this period; and

(c) what steps have been taken by Government for quick disposal of pending cases?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI BINDESHWARI DUBEY): (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the table of the House.

दिल्ली में भू-खंड उपलब्ध कराने की योजना

238. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में "रोहिणी योजना" के समान कोई योजना बनाने